भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 372

दिनांक 08 **दिसम्बर**, 2022

किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (सतत) योजना के अंतर्गत लक्ष्य

†372. **श्री राहुल रमेश शेवाले** :

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :

श्री चंद्र शेखर साहू :

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (सतत) योजना के अंतर्गत 5,000 संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना में वर्ष 2023 तक 15 एमएमटी संपीड़ित जैव गैस के उत्पादन का लक्ष्य पाने की परिकल्पना की गई है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को राजसहायता/केंद्रीय वित्त सहायता वापस ले ली है;

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सभी प्रकार के बायोगैस संयंत्रों पर राजसहायता वापस लेने से भारत के जीवाश्म ईंधन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और 50 मिलियन किसान प्रभावित होंगे;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) देश को जीवाश्म ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) और (ख) किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल की की शुरुआत अक्टूबर, 2018 में की गई थी जिसमें वर्ष 2023-24 तक सीबीजी का प्रतिवर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) उत्पादन करने के लिए 5000 संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 की स्थिति के अनुसार सतत में भागीदारी करने वाली तेल और गैस विपणन कम्पनियों ने उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित सीबीजी की अधिप्राप्ति करने के लिए 3694 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए हैं। इसके अलावा, एलओआई धारकों द्वारा प्रतिवर्ष 225 एमटी की स्थापित क्षमता वाले 38 सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों को चालू किया गया है।

(घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रमों के चरण-I की अम्ब्रैला योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को उपलब्ध राजसहायता/केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, की अवधि को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) देश की जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं यानीतिगत पहलें की हैं और बायो-ईंधनों को प्रोत्साहन, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण, रिफाइनरी प्रक्रिया संवर्धन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कार्यनीति अपनाई है।

****